वर्ष 2 अंक 7 जुलाई 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

वेंकटरमण का बजट

आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने जो भाषण दिया वह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अर्थव्यवस्था भंग हो गयी है, हालांकि मंत्री महोदय ने अपनी पार्टी को बचाते हुए इसकी जिम्मेदारी जनता सरकार के कुप्रबंध पर डाल दी.

"आर्थिक मोर्चे पर बिजली, कोयला और रेल के क्षेत्र में सबसे गंभीर कमी रही—कोयले की कमी और उसकी घटिया क्वालिटी, नाकाफी **सार-संभाल**, साज-सामान का नुकसान और इन सब कारणों से योजना और गैरयोजना व्यय में बेतहाशा बढ़ोतरी और घटिया प्रबंध आदि के कारण ताप बिजली की कुल क्षमता का उपयोग केवल 45% रह गया". इस बार श्रमिक विवादों का जिक्र नहीं किया गया है. भाषण से यह सचाई उभर कर सामने आती है कि भ्रष्टाचार और दूसरी बुराइयों के कारण बिजली का उत्पादन कुल क्षमता का 45% रह गया जिससे जनता को बेहद तकलीफें उठानी पड़ीं.

"कोई अचरज नहीं कि आधारभूत ढांचे की गंभीर कमियों के कारण इस्पात, सीमेंट, सूती कपड़े और चीनी जैसी प्रमुख चीजों के उत्पादन में 28% कमी आ गयी".

बढ़ती बेरोजगारी

इस सब का नतीजा यह निकला कि बेरोजगारी और बढ़ गयी और पिछले साल यह 9% से भी अधिक रही. बेरोजगार दफ्तर के चालू रजिस्टर के मुताबिक जनवरी 1979 में बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 31 लाख 50 हजार थी जबकि 9.8% के अनुपात से बढ़ती हुई वह साल के अंत तक 1 करोड़ 44 लाख 40 हजार तक पहुंची.

अर्थव्यवस्था में स्थिरता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1971 और 1979 के बीच निजी क्षेत्र में केवल 5 लाख नये लोगों को रोजगार मिला और सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी संख्या 40 लाख रही.

व्यापार का अंतर

वित्तमंत्री ने भुगतान के अंतर की बुरी हालत के अन्य कारण बताऐ. तेल और उर्वरक आदि आयात की जाने वाली चीजों की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण आयात खर्च बढ़ गया.

इसका नतीजा यह हुआ कि इस वर्ष व्यापार का अंतर 2232 करोड़ रु० है जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है. इसे देखते हुए भूखे भारत की "गरीबी हटाओ" का नारा देने वाली सरकार ने दस लाख टन चावल का निर्यात करने का फैसला किया है. इसके अलावा देश को 200 करोड़ रुपये के मूल्य के प्रोटीन भोजन—मछली—का निर्यात करना पड़ेगा. अर्थव्यवस्था भंग हो जारी है तो ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं.

विश्व मंडी में रहना है तो चावल का निर्यात करो, मछली का निर्यात करो, चीनी का निर्यात करो— चाहे तुम्हारे अपने

बी० टी० रणदिवे

देशवासी 8 रु० किलो के भाव से चीनी क्यों न खरीदें— और पूंजीपति वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए इस्पात, कोयले, खाने के तेलों और न जाने किस-किस चीज का आयात करो. **क्या वित्तमंत्री के पास भारत को मौजूदा स्थिति से उबारने का कोई उपाय है? जी नहीं. उनके पास तो एक ही काम है— जनता सरकार को पानी पी-पी कर कोसते रहने का.**

मुद्रास्फीति में बढ़ती

यही नहीं, 1400 करोड़ रु० के घाटे की कोई व्यवस्था न करके इस बजट में इस बात का पक्का इन्तजाम कर दिया गया कि मुद्रस्फीति बढ़ती रहे और लोगों की खाल उतरती रहे. गुजरे सालों के बजट भी इस बजट की भांति ही भारी घाटे के बजट रहे हैं. वित्तमंत्री का यह दावा निस्सार लगता है: "मौजूदा घाटा पिछले साल के घाटे की तुलना में आधे से कुछ ही ज्यादा है. मेरी धारणा हैं कि इस तरह के घाटे का अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा".

यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि इस घाटे के बजट से पहले ही रेल के मुसाफिरों के किराये और माल भाड़े में वृद्धि की जा चुकी थी और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी

की वशर से सड़क परिवहन महंगा हो गया था— इसके कारण अनेक चीजों का महंगा होना और मुद्रस्फीति की प्रक्रिया में तेजी आना लाजमी है.

इस बात को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बिना पूर्ति वाले घाटे की यह रकम 1400 करोड़ रु० सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि 800 करोड़ रु० के विदेशी कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोश से मिलनेवाले 540 करोड़ रु० को बजट में आय की मद में डाल दिया गया है, और यह रकम भी लगभग इतनी ही बैठती है. यदि ऐसा न किया गया होता तो या तो घाटा दुगुना हो गया होता अथवा योजना व्यय में भारी कटौती करनी पड़ती.

प्रेस और सरकारी हिमायतियों ने एक सुर टैक्स से राहत देने वाले बजट प्रस्तावों की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिये हैं.

पहली बात तो यह कि इन रियायतों का मूल्यांकन इस रोशनी में करना होगा कि तेल की कीमतें बढ़ाकर 2000 करोड़ रु०, रेलों का माल भाड़ा बढ़ा कर 200 करोड़ रु० और भाड़ा बढ़ा कर 200 करोड़ रु० और उर्वरक महंगे करके 300 करोड़ रु० का भार जनता पर डाला गया है इसलिए वित्तमंत्री का यह दावा गलत होगा कि उनका बजट सिर्फ इस आधार पर मुद्रास्फीति विरोधी है कि उन्होंने अपने बजट में भारी करों के प्रस्ताव नहीं रखे हैं.

झूठे दावे

और देखिए क्या-क्या दावे किये गये हैं? बजट में व्यक्तिगत आमदनी पर लगनेवाले आय कर पर छूट की सीमा 10,000 से बढ़ा कर 12,000 कर दी गयी है. यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि कर्मचारियों और मजदूरों के इस वर्ग का वास्तविक वेतन बढ़ती हुई महंगाई के कारण कम होता जा रहा था और इस वर्ग को राहत की सख्त जरूरत थी. लेकिन अजीब बात है कि अब भी वित्तमंत्री ने सिर्फ 8000 रु० की आय को कर से मुक्त रखा है. नतीजा यह होगा कि कर योग्य आय यदि 12,000 से ज्यादा हुई तो मौजूदा दर से ही आय कर लगेगा. मतलब यह कि इस रियायत से सिर्फ कुछ क्लर्कों, अध्यापकों और मजदूरों को राहत मिल सकेगी. जिनकी आय 1000 रु० महीना है उन्हें कोई लाभ नहीं होगा. जिनकी तनख्वाह इससे कम है उन्हें इससे कुछ लाभ मिल पायगा.

कुछ अच्छे कदम उठाये गये हैं— 30 जीवन रक्षक दवाओं को शुल्क से मुक्त कर दिया है; कंट्रोल के कपड़े पर उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा; गरीब "आदमियों के वाहन" साइकिल और उसके पुर्जों पर लगनेवाला उत्पादन शुल्क खत्म कर दिया गया है.

देखना यह है कुल मिला कर इन रियायतों का आम आदमी की जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ सकेगा ?

जनता पर बौझ बढ़ा

अंत में यह भी देख लिया जाय कि आम आदमी को मुद्रा के रूप में इन राहतों से कितना लाभ हो रहा है—सिर्फ 34.75 करोड़ रु० की राहत दी जा रही है, बस. जबकि 1980-81 के इस बजट में उत्पादन शुल्क से 6000 करोड़ रु० राजस्व की प्राप्ति के प्रावधान हैं.

वित्तमंत्री ने बजट में अनेक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है. उन्होंने विशेष उत्पादन शुल्क 1/20 के बदले 1/10 कर दिया है. लगता है चीनी पर लगनेवाली विशेष उत्पादन लेवी पुरानी दर पर जारी रहेगी. वित्तमंत्री के इन प्रस्तावों से केंद्रीय उत्पादन शुल्क में 223 करोड़ रु० और सीमा शुल्क में 39.58 करोड़ रु० की बढ़ोतरी होगी.

कंप्यूटर का प्रहार

वित्तमंत्री ने डाक के लिफाफों और पार्सलों पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है. लिफाफा 30 के बदले 35 पैसे का होगा. 500 ग्राम के पार्सल पर 1·50 रु० के बदले दो रु० लगेंगे. टेलीफोन लगाने और स्थानांतरित करने का खर्च बढ़ा दिया गया है. 5000 से ज्यादा स्थानीय कालों पर अब 40 के बदले 50 पैसे लगेंगे. अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से राजस्व में 27·10 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी.

देश में बननेवाले कंप्यूटरों पर उत्पादन शुल्क 25% से घटाकर 20% कर दिया है. इससे बेकारी में बढ़ोतरी के अलावा और कुछ नहीं होगा. और जगह तो वित्तमंत्री लघु उद्योगों को सहायता देने तथा पूंजी की रोजगार क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन यहां के कंप्यूटरों को बढ़ावा दे रहे हैं. कंप्यूटरों से मजदूरों और कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर भयंकर असर पड़ेगा. सच तो यह है कि सरकार श्रम-प्रधान उद्योगों की बात महज दिखावे के लिए करती है अन्यथा मजदूरों की रोजी-रोटी पर हमला करने का फैसला तो पहले ही लिया जा चुका है. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों में कम से कम 10% कटौती का फैसला कर चुकी है उधर निजी और सार्वजनिक उद्योग उत्पादन लागत घटाने के लिए कंप्यूटरों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

इस बढ़ोतरी के लिए दी गयी दलीलें एकदम लचर हैं. वित्तमंत्री का कहना है कि डाकतार कर्मचारियों को बोनस देने के कारण यह बढ़ोतरी लाजिमी हो गयी थी. यह बड़ी बेहूदा दलील है. पहली बात तो यह है कि यह बोनस उत्पादकता के साथ जुड़ा हुआ है. दूसरी बात यह है कि डाक- तार विभाग इसके लिए पहले ही रास्ता बना चुका है. विभाग ने तय किया है कि रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां नहीं की जायेंगी. डाकतार विभाग के स्टाफ में 7% कटौती तो पहले ही की जा चुकी है. इस तरह बोनस देने के बावजूद विभाग को बचत होगी. इसके अलावा जनाब वेंकटरमण ने सदन को यह नहीं बताया कि संचार मंत्रालय भी अपने विभाग के कर्मचारियों में 10% कटौती करने की फिराक में है.

[शेष पष्ठ दस पर]

इजराइल द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों का दमन

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

इजराइल ने कब्जा लिए गए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अपनी कृषि और उद्योगों के लिए सस्ती मजदूरी का स्रोत बना दिया है. वहां की आर्थिक हालत को जड़ कर दिया है. और अपनी संकटग्रस्त हालत के लिए इन क्षेत्रों को विदेशी मुद्रा का साधन बना दिया है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 65वें अधिवेशन में पेश की गई हाल ही की एक आई. एल. ओ. रिपोर्ट में इजराइल द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों में मजदूरों की हालत पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है. इस रिपोर्ट की बहुत ही चौका देने वाली कुछ बातों को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं.

आर्थिक निर्भरता

इन क्षेत्रों की मंडियों के द्वार इजराइली मंडियों के लिए खोल दिए गए हैं. उन पर इजराइल का बाह्य कर थोप दिया गया है जिससे यहां 90% आयात इजराइल से होता है. इसके नतीजतन 1977 में 12 करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा हुआ और यह इजराइल के फायदे में गया. विदेशों में काम कर रहे फिलिस्तीनियों की कमाई से यह घाटा पूरा किया जा रहा है. मौजूदा आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हैं.

असुरक्षित उत्पादन

कब्जाए गए क्षेत्रों में इजराइली वस्तुओं से होड़ के खिलाफ स्थानीय वस्तुओं को इजराइल द्वारा की जाने वाली सप्लाई पर निर्भरता और उपयुक्त मंडियों व कर्ज व पैसा लगाने के लिए बैंक प्रणाली की कमी से कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है. इन कब्जाए गए क्षेत्रों में अरब परियोजनाओं के लिए कर्ज व आर्थिक सहायता देने से इजराइली बैंक इनकार कर देते हैं. अरब देशों से अनुदान के आयात को रोकने के लिए भी जबरदस्त अड़चनें पैदा की जाती हैं. कृषि क्षेत्र में, अरब किसानों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्हें इजराइली कृषि से मुकाबला करना पड़ता है जिसका उत्पादन भी ज्यादा है तथा आर्थिक सहायता भी मिलती है. इस क्षेत्र को अब तीन अन्य दिशाओं से भी चुनौती मिल रही है : कब्जाई गई अरब भूमि पर इजराइलियों ने रहन-सहन शुरू कर दिया है जिससे उपजाऊ भूमि कम होती जा रही है, पानी की कमी क्योंकि वेस्ट बैंक के जल-स्रोतों को इजराइल अपने लिए इस्तेमाल करता है, और मजदूरों की जबरदस्त कमी, क्योंकि कब्जाए गए क्षेत्रों के मजदूरों को इजराइल अपने लिए इस्तेमाल करता है.

ईस्ट (अरब) जेरूसलम को अपने में मिलाने के कारण पर्यटन से मिलने वाले राजस्व में भारी गिरावट आई है. वेस्ट बैंक की आय का परंपरागत बड़ा स्रोत यह स्थान इस क्षेत्र की गति-विधियों का मुख्य केंद्र रहा है और पवित्र स्थानों व ऐतिहासिक स्थलों के कारण यह पर्यटन के लिए मुख्य आकर्षण रहा है. इजराइल के आर्थिक व व्यापारिक ढांचे के साथ इसे मिला लेने ने कब्जाए गए क्षेत्रों के विकास पर नकारात्मक असर डाला है. 1967 में इसको मिलाने से पहले ईस्ट जेरूसलम में पर्यटक अनुमानतः 17 करोड़ रुपये सालाना खर्च करते थे जो वेस्ट बैंक के कुल आयात का एक-तिहाई भाग है.

रोजगार स्थिति

ईस्ट जेरूसलम को छोड़कर कब्जाए गए क्षेत्रों का लगभग 18 लाख जनता में से केवल एक लाख 46 हजार लोग 1978 में कब्जाए गए क्षेत्रों की श्रम मंडी में थे. यानि काम योग्य उम्र की जनता का केवल 23% या क्षेत्र की मौजूदा कार्यशील जनता का 70% से भी कम. बाकी 30% इजराइली अर्थव्यवस्था में काम करते हैं.

रोजगार न मिलने के कारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई है जिसके नतीजतन लगभग 20,000 युवक, कुशल और व्यावसायिक मजदूर हर साल रोजगार की तलाश में अन्यत्र चले जाते हैं.

इजराइल में अरब मजदूर

कब्जाए गए क्षेत्रों के इजराइल में लगे 1978 के आंकड़ों के अनुसार 75,000 मजदूरों का हालत और भी गंभीर है. ज्यादातर मजदूरों को ऐसे व्यवसायों जैसे घरेलू कार्य आदि में अस्थायी तौर पर लगाया जाता है जिनके लिए इजराइली मजदूर नहीं मिलते. इन मजदूरों को निम्नतम वेतन मिलते हैं. इजराइल के निर्माण क्षेत्र में 1975 में मंदी के दौरान 9000 अरब मजदूरों को निकाल दिया गया और उन्हें कोई और रोजगार भी नहीं मिला. उनका ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा रहा है. इसके नतीजतन "एक गुप्त मंडी···जिसमें मजदूरों का वस्तु की तरह व्यापार होता है" बन गई हैं. कब्जाए गए क्षेत्रों से इजराइल में अनियमित तौर पर कार्य करने वाले मजदूरों में से लगभग 20% अल्पवयस्क हैं, जो कृषि या छोटे उद्योगों में अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए काम करते हैं.

रोजगार स्थिति

इन क्षेत्रों के अरब मजदूरों को इजराइल में काम करने के लिए अस्थायी कार्य परमिट दिए जाते हैं जिनका उन्हें हर चौथे महीने नवीनीकरण करना होता है. इसके उल्लंघन का मतलब है जुर्माना व जेल. परमिट से इजराइल में सोने या रहने की इजाजत नहीं मिलती और उन्हें हर रोज लंबी दूरी तय करके कब्जाए गए क्षेत्रों में ही वापस जाना पड़ता है.

आई. एल. ओ. की रिपोर्ट ने फिलिस्तीनी मजदूरों में असमानता व पृथकता की बढ़ रही भावना को और उनके पहचान व व्यक्तिगत सम्मान को मान्यता की जरूरत को नोट किया. संक्षेप में रिपोर्ट यह दिखाती है कि इजराइल समानता, स्वतंत्रता और मानव सम्मान के सभी मानों का उल्लंघन करता है और इन क्षेत्रों को अपने में मिलाने के अपने इरादे को और मजबूत करता है.

ब्रिटेन में प्रभावशाली 'संघर्ष दिवस'

रोजगार विधेयक के नाम पर टोरी सरकार एक ऐसा कानून बना रही है जिसके तहत सेकेंडरी पिकेटिंग, यानि जिस फैक्ट्री में हड़ताल हो उसके अलावा दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों द्वारा समर्थन में पिकेटिंग करने आदि पर रोक लगा दी जाएगी. और इस नियम का उल्लंघन करने वाले को असीमित जुर्माना और जेल सजा दी जाएगी. ब्रिटिश ट्रेड यूनियन सेंटर (टी यू सी) का कहना है कि यह विधेयक अनुचित, गैरजरूरी और खतरनाक है तथा औद्योगिक संबंधों की समस्याओं को सुधारने की बजाए यह उन्हें और अधिक जटिल बनाएगा.

टी. यू. सी. ने टोरी सरकार की आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध जाहिर करने और जनता को सचेत करने के लिए 14 मई को 'संघर्ष दिवस' आयोजित किया. लेकिन इस आह्वान के प्रति प्रचार साधनों (जैसे समाचार पत्र व रेडियो) का रवैया अच्छा नहीं था.

स्काटलैंड व वेल्स में बहुत ही काम परिवहन देखा गया तथा खदानों में कोई उत्पादन नहीं हुआ. अनुमानत: 2 लाख 50 हजार स्काटिश मजदूरों ने टूल डाउन कर दिया. फ्लीट स्ट्रीट में कोई समाचार पत्र नहीं छपा और अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया. लंदन में छापाखानों के मजदूरों का जुलूस सबसे बड़ा था. उत्तरपूर्व में नाम के लिए परिवहन था. देश में ज्यादातर केवल संघीय रेल सेवा ही उपलब्ध थी.

इस दिन लिवरपूल, मानचेस्टर और हुल्ल में बदरगाहों में कोई काम नहीं हुआ. आमतौर पर सभी कोयला मजदूर हड़ताल पर थे और 66,000 यर्कशायर के खदान मजदूरों में से 62,000 मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया. स्काटलैंड में केवल एक को छोड़कर सभी शिपयार्ड बंद रहे. अध्यापकों के बड़े संगठन, एन. यू. टी., ने आधे दिन काम न करके प्रतिरोध में भाग लिया. इसके अलावा समूचे देश में सैंकड़ों मीटिंगें अयोजित की गईं और सैंकड़ों हजारों मजदूरों ने जूलूसों में भाग लिया.

आई. एल. ओ. सम्मेलन का बहिष्कार

नामजदगी के बारे में सरकार के एकतरफा फैसले के कारण चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, सीटू, एटक, एच. एम. एस. और बी. एम. एस. ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) के हाल ही में हुए अधिवेशन के लिए श्रमिक प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने से इनकार कर दिया. बड़ी तुर्ता फुर्ती में इंटक को इसके लिए नामजद किया गया था और श्रमिक प्रतिनिधिमंडल के एक सर्वमान्य मंडल तय करने की संभावनाओं की भी खोज नही की गई.

इन चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार की इस कार्यवाही के विरुद्ध अपना प्रतिरोध जाहिर किया हैं. और क्योंकि सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को 28 अप्रैल को लिखे गए श्रम मंत्री के पत्र का उत्तर पाने के लिए उचित समय तक इंतजार नही किया. अपने पत्र में श्रम मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि बारी बारी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर अगले वर्ष विचार किया जा सकता है क्योंकि इस बारे में आम राय होने में अभी और समय लगेगा. इसी दौरान श्रम मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा कि इंटक के प्रतिनिधि को डेलीगेट नामजद किया जाना चाहिए और सीटू, एटक एच. एम एस. और बी. एम. एस. के प्रतिनिधि सलाहकार होने चाहिये.

पिछले साल सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को यह कहा था कि आई. एल. ओ. प्रतिनिधिमंडल के लिए क्रमानुसार सिद्धांत को मान लिया जाएगा. सरकार इस वादे से पीछे हट गई है. श्रम मंत्री को लिखे गए एक पत्र में चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अपनी राय व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल से भारतीय श्रमिक प्रतिनिधिमंडल की साख ऊंची होती. ध्यान रहे कि हमारे देश में मालिकान के संगठन अपना प्रतिनिधिमंडल बारी बारी के सिद्धांत पर भेजते हैं.

विकासशील देशों में बेरोजगारी का बढ़ता खतरा

दुनिया के 121 करोड़ काम करने योग्य लोगों का दो तिहाई हिस्सा विकासशील देशों में बसा हुआ है (इन आंकड़ों में चीन शामिल नहीं है). विकसित देशों में लगभग 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं या अर्धरोजगार वाले हैं.

हाल ही के आइ. एल. ओ. के शोध के अनुसार दुनिया में श्रम शक्ति 1.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है. किन्तु विकासशील देशों में श्रमशक्ति की यह बढौतरी इससे कही अधिक— 2.5 प्रतिशत है.

देखना यह है कि तीसरी दुनिया में स्थित इस बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी के विरुद्ध एक सफल मोर्चा कायम करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी.

इस बारे में सही आंकड़े दे पाना मुश्किल है क्योंकि आंकड़े प्रत्येक देश के आर्थिक ढांचे, इसके विकासस्तर और तकनीकी विकल्पों पर निर्भर करते हैं. आइ. एल. ओ. का अनुमान है कि विकासशील देशों के मौजूदा हालात में नई नौकरी के लिए एक स्थान बना पाने के लिए औसतन 50,000 रुपयों की आवश्यकता है.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

पुलिस दमन के खिलाफ उत्तर रेलवे के लोकोकर्मियों द्वारा हड़ताल

जींद के लोको रनिंग स्टाफ ने 7 जून को अचानक प्रतिरोधात्मक हड़ताल कर दी, क्योंकि एक रेल के ड्राइवर बनवारी लाल को गालियां दी गई, थप्पड़ मारा गया और एस. एच. ओ. द्वारा उसे शराबी होने के नाम पर डाक्टरी परीक्षा के लिए भेज दिया गया. यह दरअसल यात्रियों के रोष के कारण और 1945 में बने पुराने सी. डब्ल्यू. डी इंजन को चलाकर रेल सेवा का चालू रखने की पूरी कोशिश कर रहे लोको रनिंग स्टाफ की रक्षा करने की बजाय अपने अधिकार का गलत उपयोग करने तथा ड्यूटी पर दूसरे सार्वजानिक कर्मचारी के साथ हाथापाई करने के कारण हुआ लोकोकर्मियों ने सुरक्षा और एस. एच. ओ. के खिलाफ कार्यवाही की मांग की.

दिल्ली के डिविजनल रेलवे मैनेजर ने अपने कर्मचारी की ओर से हस्तक्षेप करने की बजाए सख्त रवैया अपनाया तथा कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया.

दिल्ली का लोको रनिंग स्टाफ 8 जून को एकजुटता कार्यवाही में कूद पड़ा और रेलवे अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि 48 घंटों के अदंर मांगें स्वीकार नहीं की गईं तो समूचा नार्दर्न जोन एकजुटता कार्यवाही करेगा. सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने संघर्ष के समर्थन में एक बयान जारी किया. लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नही दिया और संघर्ष को छिन्न-भिन्न करने की पूरी कोशिश की.

केवल 10 जून को यह घोषणा की गई कि इस घटना की मैजिस्टेरियल छानबीन कराई जाएगी. लोकोकर्मियों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि एस. एच. ओ. द्वारा गवाहों पर प्रभाव डालने आदि की संभावना थी और इसलिए उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष छानबीन के लिए एस. एच. ओ. का यहां से तबादला कर दिया जाए.

इसी दौरान अधिकारियों ने मद्रास व सिकदराबाद से टेरीटोरियल आर्मी (क्षेत्रीय सेना) को हवाई जहाज द्वारा बुला भेजा और रेल सेवा में काम करने वाले कर्मचारी को 1000 रूपये नकद, दुगने भत्ते व उसके एक बच्चे को नौकरी देने की पेशकश की. अधिकारियों ने प्रशिक्षण पाने वालों को प्रशिक्षण स्कूलों से वापस बुलाकर रेल सेवा में लगा दिया तथा रेलें चलाने का कार्य अशिक्षित कर्मचारियों को सौंप दिया.

लोको कर्मियों ने बहादुरी के साथ अपना संघर्ष जारी रखा और मुरादाबाद, फिरोजपुर, बिकानेर और जोधपुर डिविजनों के कर्मचारी भी एक के बाद एक एकजुटता कार्यवाही में जुट पड़े. इलाहाबाद और लखनऊ डिविजनों के कुछ भाग भी प्रभावित हुए.

रेलमंत्री द्वारा शीघ्र समझोते की अपील का लोको रनिंग स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया और जनरल मैनेजर तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से तुरंत समझौते के लिए मिले. इस बातचीत के दौरान उन्होंने यह आश्वासन दिया कि रेलवे अधिकारी एस. एच. ओ. के तबादले के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध करेंगे. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी को भी तंग नही किया जाएगा और जो कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है उसकी सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा की जाएगी. यह ढुल-मुल बात लोको कर्मियों को स्वीकार्य नहीं थी इसलिए वे रेल राज्यमंत्री से मिले जिन्होंने लोकोकर्मियों को आश्वासन दिया कि यदि बाद में कोई दिक्कत आएगी तो समाधान के लिए उनसे (मंत्री) बातचीत की जा सकती है.

इस आश्वासन पर लोको नेताओं ने कहा कि एल. आर. एस. जी. सी. नार्दर्न रेलवे को भी समझौता वार्ता के लिए बुलाया जाए ताकि फैसला औपचारिक रूप से लिया जा सके. इस बात को सब तक पहुंचाने में देर हो गई और सभी सदस्य समय पर नहीं पहुंच सके. लेकिन क्योंकि संगठन के जोनल अध्यक्ष और सेक्रेटरी व अन्य महत्वपूर्ण नेता वहां मौजूद थे 16 जून को संघर्ष वापस ले लिया गया. लेकिन उसके तुरंत बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने एक बयान जारी किया जिसने सामान्यता में खलल डाली.

अंबाला छावनी में जब मजदूर जुलूस की शक्ल में ड्यूटी पर जा रहे थे तो उन्हें अचानक सी. आर. पी. ने घेर लिया और नेताओं को बेरहमी से पीटा. पास खड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा गया. यह बदले की भावना से था क्योंकि लोकोकर्मी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. यहां भी हरियाणा पुलिस ने यह वहशियाना और बदले की भावना से हमला किया. दस लोग गिरफतार किए गए जिसमें एक टिकट कलेक्टर और एक शंटर का बेटा भी था जिनका न तो संघर्ष से ही कोई लेना देना था और न ही जुलूस से. ड्यूटी के लिए लोकोशेड जाने वाले सभी कर्मचारी तुरंत वापिस हो लिए और अपना संघर्ष जारी रखा. एल. आर. एस. ए. की दिल्ली डिविजन के कार्यकारी अध्यक्ष को गंभीर चोटें आईं और जिसके लिए उन्हें रेलवे हस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें हथकड़ी लगाकर हस्पताल के बिस्तरे के साथ बांध कर रखा गया. पुलिस ने मनघड़ंत आरोप लगाए ताकि जमानत में दिक्कत आए. लेकिन मजदूरों ने अपने साथियों के बिना काम पर जाने से इनकार कर दिया. अंबाला छावनी में हड़ताल 21 जून तक वापस नहीं ली जा सकी.

नार्दर्न जोनल एल. आर. एस. ए. के अध्यक्ष एस. आर. बग्गा ने अंबाला छावनी

[शेष पृष्ठ छः पर]

रेल समाचार...

[पृष्ठ पांच से आगे]

का दौरा किया और वह पुलिस व सिविल अधिकारियों से मिले तथा उन्हें बताया कि यदि वे भिडंत के इस रवैये को जारी रखेंगे तो समूची नार्थ जोन एल. आर. एस. ए. प्रतिरोध कार्यवाही करेगी. इससे कुछ प्रभाव पड़ा और गिरफ्तार किए गए नेताओं को जमानत पर छोड़ दिया गया. मजदूरों ने छूटकर आए नेताओं का स्वागत आयोजित किया और जुलूस बनाकर ड्यूटी पर गए. पुलिस ने लारियों व अन्य गाड़ियों से जबरदस्त गश्त लगाकर मजदूरों को आतंकित करने की कोशिश की. लेकिन मजदूरों ने इस सब की परवाह नहीं की और एस. आर. बग्गा के नेतृत्व में शांतिपूर्वक जुलूस का आयोजन किया और इस प्रकार हड़ताल वापस ली गई.

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब अधिकारी अपने वायदे से पीछे हट गए हैं. आत्म सुरक्षा के किसी भी मौके को दिए बिना सख्त सजाएं दी जा रही हैं. कई ड्राइवरों को, जिन्हें पहले एस्टेब-लिशमेंट कोड के नियम 14(ii) के तहत निकाला गया था, अब क्लीनरों की जगह दी जा रही है जो पांच स्तर नीचे हैं. इसलिए लोकोकर्मियों में रोष फिर से फैल रहा है.

इस बात का भी जिक्र जरूरी है कि लोको मकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन, सी एंड डब्ल्यू स्टाफ काउंसिल और अन्य विभिन्न संगठनों ने संघर्ष का समर्थन किया तथा अधिकारियों को इस बात की सूचना दी कि यदि मुद्दे का हल नहीं हुआ तो वे भी इस संघर्ष में शामिल हो जाएंगे.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को 23 जून को मिलने वाले अखिल भारतीय नेताओं ने अधिकारियों के इस रवैये पर विरोध प्रकट किया और उनको बताया कि यदि पहले दिए गए आश्वासन को अधिकारी पूरा नहीं करते हैं तो अखिल भारतीय संगठन को कदम उठाना पडेगा और संघर्ष अवश्यंभावी हो जाएगा. वे रेलवे बोर्ड कों अध्यक्ष के साथ वेतन मानों, काम के घंटों और रनिंग आलाउंस में संशोधन पर बातचीत कर रहे थे.

पूर्वी रेलवे में आंदोलन

पूर्वी रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ ने 23 मार्च 1979 के समझौते के बाद एक साल से भी ज्यादा इंतजार करने के बाद अधिकतम दस घंटे की ड्यूटी लागू कराने के लिए एक जून से आंदोलन शुरू कर दिया है. अधिकारी समय से सुविधाएं प्रदान नहीं कर सके जिसकी वजह से 200 से भी ज्यादा ट्रेनों को स्थिर करना पड़ा. जब आंदोलन को शुरू किया गया तब ही अधिकारियों ने कुछ कलीनरों को भर्ती किया और लोकोकर्मियों की स्टाफ संख्या में वृद्धि की.

दक्षिण पूर्वी रेलवे के लोकोकर्मी भी संघर्ष पर

दक्षिण पूर्वी रेलवे की रेल सेवा को बिलकुल भिन्न कारण की वजह से 18 जून को ट्रेड यूनियन कार्यवाही का सामना करना पड़ा. ए. आई. एम आर एस. ए. के पहले फैसले के अनुसार इस दिन डिविजन स्तर का प्रदर्शन आयोजित करना था. एस ई आर अधिकारियों ने अचानक एक निदेश जारी किया कि इस दिन कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी. इस गैर जरूरी प्रतिबंध से इतना अधिक रोष फैला की उन्होंने लिखित रूप में एक दिन की छुट्टी मांगी और प्रदर्शन में भाग लिया जिससे कई मालगाड़ियों की सेवाओं को रद्द करना पड़ा.

स्टेशन मास्टरों का अखिल भारतीय सम्मेलन

आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसो-सिएशन का सम्मेलन 24-25 मई को त्रिवेंद्रम में हुआ. केरल की वामपंथी-जनवादी सरकार की मंत्री के. आर. गौरी अम्मा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर प्रकाशित सोवेनियर का अनुमोदन किया. विभिन्न ट्रेड यूनियन नेतओं ने सम्मेलन को शुभकामनाएं दीं.

एसोसिएशन ने 26 जून को एक गोष्ठी आयोजित की जिसका उद्घाटन सुशीला गोपालन, एम. पी. ने किया तथा अन्यों के अलावा मैथ्यू क्यूरियन तथा सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने इसको संबोधित किया. के. सी. राय चौधरी अध्यक्ष और के. शिवन पिल्लै एसोसिएशन के महासचिव चुने गए.

ए. आई. आर. एफ. ने सिद्धांततः कंप्यूटर माना

ए. आई. आर. एफ. की बर्किंग कमेटी की 10-11 जून को जम्मू में हुई बैठक में हुई बातचीत से यह पता चलता है कि ए. आई. आर. एफ. ने मौजूदा आई. बी. एम. 11401 कंप्यूटर की जगह तीसरी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को स्वीकार कर लिया है जो न केवल कार्यालयों के लिए लाया जाएगा बल्कि कई प्रकार की रेल सेवा गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा. इस प्रकार यह साफ जाहिर है कि देश के सबसे बड़े उद्योग में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे जो पहले ही कम हो चुके हैं, जबकि देश में रोजगार केंद्रों के आंकडों के अनुसार एक करोड़ 50 लाख बेरोजगार मौजूद हैं.

दि वर्किंग क्लास

सी आई टी यू का अंग्रेजी मासिक

एक प्रति की कीमत 50 पैसे

वार्षिक चंदा छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय,
, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

पश्चिम बंगाल समाचार

केशोराम कपड़ा मिल में तालाबंदी खत्म

कलकत्ता की बिरला केशोराम कपड़ा मिल के दस हजार मजदूर और कर्मचारी पिछले पांच महीने से मिल में प्रबंधकों द्वारा 13 जनवरी से लागू तालाबंदी के खिलाफ संघर्षरत थे. 144 दिन की यह तालाबंदी राज्य श्रम मंत्री कृष्णपद घोष की अगुवाई में हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद 5 जून को खत्म कर दी गई. समझौते के तहत प्रबंधकों ने उन मजदूरों को दोबारा भर्ती करना मंजूर कर लिया है जिनकी छंटनी कर दी गई थी और साथ ही प्रत्येक मजदूर को 200 रुपये की तदर्थ राशि देना भी स्वीकार कर लिया है. संघर्ष में भाग लेने वाले किसी भी मजदूर को प्रबंधकों की नीतियों का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा और जो मजदूर राज्य के बाहर गए हुए हैं उन्हें दोबारा मिल में आने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाएगा.

मजदूरों ने इस संघर्ष का नेतृत्व सीटू और एटक की यूनियनों ने किया था. सीटू और एटक के आह्वान पर उस क्षेत्र की अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों और कर्मचारियों ने पहले 'एकता दिवस' मनाया और बाद में केशोराम के संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की.

हिन्दुस्तान पिलकिंगटन की तालाबंदी के खात्मे की मांग

आसनसोल में हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्कस (जो एकाधिकारी थापर घराने के नियंत्रण मे है.) के प्रबंधकों ने मजदूरों में अनुशासनहीनता होने के नाम पर 25 मई को फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी. सीटू, एटक और इंटक की यूनियनों ने एक हो कर इस गैर कानूनी तालाबंदी के तुरन्त खात्मे की मांग की है. उनके अनुसार यह तालाबंदी पूर्व निश्चित थी क्योंकि प्रबंधक थापर वालों को इस फैक्ट्री का पूरा नियंत्रण सौंपना चाहते हैं. मजदूरों पर लगाया गया अनुशासनहीनता का आरोप झूठ था. प्रबंधक 1979 के त्रिपक्षीय समझौते में तय हुए कुछ मुद्दों को लागू करने से इंकार कर रहे हैं जिसके बारे में अभी तक बातचीत जारी है. प्रबंधक इस तालाबंदी का कहीं जिक्र ही नहीं करते हैं यहां तक कि हाल ही में हुई त्रिपक्षीय बातचीत में भी प्रबंधकों ने इस बात को नजर अंदाज कर दिया.

त्रिपुरा में दंगा पीड़ितों के लिए राज्य सीटू द्वारा अनुदान

सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने हाल ही के दंगों और प्रतिक्रियावादियों के सशस्त्र हमले के शिकार लोगों की सहायता के लिए त्रिपुरा मुख्यमंत्री सहायता कोष को 10,000 रुपये का अनुदान दिया. राज्य की सीटू शाखा के महासचिव मनोरंजन राय ने राज्य के मजदूर वर्ग से यह अपील की है कि वे त्रिपुरा के लोगों की सहायता के लिए अधिक से अधिक दान दें.

स्वचालन पर रोक लगाने की मांग

आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधक कम्पनी में एक ऐसा इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे चलाने के लिए प्रोग्रामर्स, आपरेटर्स, सिस्टम्स एनालिस्ट्स आदि को मिलाकर कुल 45 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी. यह कम्प्यूटर स्टोर का काम, खरीददारी का लेखा और यहां तक कि वेतन-रोल आदि को मिलाकर कम्पनी के दफ्तर का सारा काम करेगा जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के बहुत बड़े भाग की छंटनी कर दी जाएगी और रोजगार-भविष्य भी खत्म हो जाएगा.

भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी के आंकड़े 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच चुके हैं इस तरह के स्वचालित यंत्र लगाना कहां तक सही है ? इसके विरोध में सारे विश्व में और विशेषतः देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा विरोध किया जा रहा है. ई. सी. एल. प्रबंधकों के हाल ही में उठाए गए कदम के विरोध में बहुत से सम्मेलन किए गए. हाल ही में 19 अप्रैल को सेंक्टोरिया में हुए सम्मेलन में कामगार जनता के हर हिस्से और सभी ट्रेड यूनियनों से अपील की गई है कि वे यत्रीकरण के विरुद्ध एक होकर राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मोर्चा तैयार करें जिससे नौकरी की सुरक्षा, रोजगार और जीवन स्तर पर हुए घातक हमलों को मुंह की खानी पड़े.

ई. सी. एल. कोलरी की सीटू, एटक, यूटक, एच. एम. एस. और इंटक सभी ट्रेड यूनियनों ने कम्प्यूटर का डट कर विरोध करने का फैसला किया है. इन सभी यूनियनों ने मिलकर ई. सी. एल. के सी. एम. डी. और श्रममंत्री को एक ज्ञापन दिया है और उनसे अपील की है कि यंत्रीकरण की इस योजना को खत्म किया जाए.

जल परिवहन मजदूरों का संयुक्त मांगपत्र

हाल ही में जल परिवहन मजदूरों की चार फेडरेशनों ने जिसमें वाटर टांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया (सीटू) भी है, मिलकर मांग पत्र पेश किया है. इस मांग पत्र में संशोधित वेतन मानों और मंहगाई की पूरी भरपाई भी शामिल है. अन्य मांगे इस प्रकार हैं— अतिरिक्त कार्य भत्ता, रात्रि भत्ता, समान काम का समान नाम, उचित वर्गीकरण, पदोन्नति, पांच दिनों का सप्ताह, सभी गोदी व बंदरगाह मजदूरों के लिए 20% बोनस, सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं जैसे रिटायरमेंट आदि की, जख्मी होने पर काम करने योग्य न हो पाने तक सवेतन छुट्टी, छुट्टी के बदले अतिरिक्त वेतन आदि शामिल है.

चाय बागान मजदूरों की जीत

6 मई को हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, राज्य के चाय बागान के लगभग 3 लाख मजदूरों के वेतन में 90 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ौतरी हुई है.

इससे 1982 में उनकी प्रतिदिन की आय 9 रुपये हो पाएगी. समझौता राज्य श्रम मंत्री कृष्णपद घोष की हाजरी में हुआ. यह तीन वर्षों तक लागू रहेगा.

पश्चिम बंगाल सीटू का तीसरा सम्मेलन

सीटू की पश्चिम बंगाल कमेटी का तीसरा राज्य सम्मेलन 27 से 30 मई तक कलकत्ता के पास दम दम में अनंत—सुनील नगर नामक एक औद्योगिक क्षेत्र में हुआ जो साहसी मजदूर वर्ग और जनवादी संघर्षों की एक लम्बी परम्परा लिए हुए है. इस क्षेत्र का नाम दम दम के दो जाने माने सीटू नेताओं अनंतदत्त और सुनील सेनगुप्त के नाम पर रखा गया जिनकी जानें अर्ध-फासिस्ट आतंक के दौर में कांग्रेस की ज्यादतियों ने लीं.

इस सम्मेलन से पांच वर्ष पहले दिसम्बर 1974 को दूसरा राज्य सम्मेलन जलपाइगुड़ी जिले के माल बाजार में हुआ था. इस तीसरें सम्मेलन में पश्चिम बंगाल में सीटू के भविष्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया. यह सम्मेलन देश में बदली राजनैतिक स्थिति-एक ओर केन्द्र में अधिनायकवादी ताकतों के दोबारा उभरने और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के अपनी अस्तित्व बनाए रखने के संदर्भ में बुलाया गया. तीन दिनों तक हुए इस सम्मेलन में मजदूर वर्ग के राजनैतिक व आनेवाले नाजुक दिनों में संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की गई.

सम्मेलन की तैयारियां महीनों पहले शुरु हो गई थीं. हालांकि स्वागत कमेटी के सचिव तरुण सेन गुप्त की अचानक मृत्यु से काफी नुकसान पहुंचा फिर भी सम्मेलन का सारा प्रबंध निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया गया. 3000 से भी अधिक प्रतिनिधियों के लिए लगाया गया एक बड़ा पंडाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ब मजदूर वर्ग के संघर्ष का इतिहास दर्शाने वाली प्रदर्शनी के लिए लगाया गया एक अलग पंडाल लगाया गया था. 2000 से अधिक वालंटियरों ने सप्ताह भर तक सारा दिन काम करके इस सम्मेलन को सफल बनाने में पूरी-पूरी सहयोग दिया.

इस सम्मेलन से राज्य के सभी मजदूरों विशेषत: बड़कपुर औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों में एक उत्साह की लहर दौड़ गई. उस जिले और राज्य के अन्य क्षेत्रों के मजदूरों से नकदी और जिन्सी दोनों तरह के अनुदान लगातार जमा किए गए.

27 मई को आरम्भ हुए इस सम्मेलन में 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने तथा सैंकड़ों बिरादराना प्रतिनिधियों व दर्शकों ने भाग लिया. आरम्भ में राज्य की सीटू शाखा के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने सीटू का झंडा फहराया तथा बाद में मोहम्मद इस्माइल, मनोरंजन राय, निरेन घोष, कमल सरकार शांति घटक तथा अन्य नेताओं ने शहीद स्मारक पर मालाएं चढ़ाई.

सम्मेलन का उद्घाटन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा कमेटी के चेयरमैन प्रमोद दास गुप्ता ने किया. एक 11 सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने कारवाई शुरु की.

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रमोद दासगुप्ता ने बताया कि किन हालात के तहत यह सम्मेलन बुलाया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के मजदूर वर्ग के लगातार बढ़ रहे कदमों को सत्ताधारी वर्ग के आंतक और दमन से कभी कुचला नहीं जा सकता है. उन्होंने प्रतिनिधियों से यह अपील की कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में मौजूद अवसरवादी तत्वों का खात्मा करें और राज्य की वामपंथी सरकार का लाभ उठाकर मजदूर वर्ग में एकता स्थापित करते हुए उनके संगठन को आंदोलन की एक सही दिशा दें.

सी. पी. आई. (एम) के महासचिव ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद, सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती तथा सी. पी. आई. (एम) की महाराष्ट्र और आसाम राज्य कमेटी तथा सीटू की कर्नाटक, पंजाब और आसाम राज्य कमेटियों के सचिवों ने सम्मेलन को अपने बधाई संदेश भेजे.

मोहम्मद इलयास (एटक), शांतिमय घोष (किसान सभा), पंकज आचार्य (महिला समिति) अरविन्द घोष 12 जुलाई कमेटी व कोआर्डिनेशन कमेटी गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज) में लोकपतिराय (ए. बी. टी. ए.), ए. पी. चटर्जी (डेमोक्रैटिक लायरस एसोसिएशन), ए. बसु (डी. वाइ. एफ.), एस. पुता तुंडा (एस. एफ. आइ.) जी जोसइ (एच. एम. एस.) और ए. राय (टी. यू. सी. सी.) ने सम्मेलन में प्रतिनिधियों का व्यक्तिगत रूप से अभिनदन किया.

महासचिव की रिपोर्ट (जो बंगाली, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित थी) सीटू पश्चिम बंगाल कमेटी के महासचिव मनोरंजन राय ने पेश की. 60 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने तीन दिनों तक चर्चा में भाग लिया जिसके बाद इस रिपोर्ट को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वीकार किया गया. कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट के साथ-साथ हिसाब किताब का लेखा भी पारित हुआ.

अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय हालात समझाते हुए रिपोर्ट में दूसरे सम्मेलन से अब तक की पश्चिम बंगाल सीटू की गति विधियों की रूप रेखा, उन समस्याओं जिनका सामना राज्य के लोग और मजदूर वर्ग कर रहा है, वामपंथी सरकार की उपलब्धियां और राज्य में उभरती मजदूर वर्ग की जुझारू कार्यवाहियों में उसकी भूमिका बताई गई है. मजदूर वर्ग के कार्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिनिधियों को चाहिए कि वर्तमान वामपंथी सरकार के अस्तित्व का फायदा उठाते हुए वे कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं और मजदूरों में राजनैतिक जागरुकता पैदा करें. साथ ही सीटू को एक मजबूत संगठन बनाने में कोई कसर बाकी न छोड़ें संगठनात्मक कार्यों में सदस्यता को 50 प्रतिशत बढ़ाना (इसकी वर्तमान सदस्यता छ: लाख से ज्यादा है), अगले तीन महीनों में 5 लाख रुपयों का अनुदान जुटा पाना, यूनियनों की जनवादी कार्यविधियों का आश्वासन देना और

संघर्षात्मक कमजोरियों पर काबू पाना है.

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 28 मई को सम्मेलन में भाषण दिया. उन्होंने मजदूर वर्ग को एक होकर बुर्जुआ जमीदारों के शोषण और हमलों तथा अधिनायकवादी ताकतों का डटकर मुकाबला करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा "सीटू को जनवाद और मजदूर वर्ग की मूल मांगों को मनवाने के लिए ट्रेड यूनियन एकता को बनाने में और अधिक सक्रिय भूमिका अदा करनी है."

राज्य के मुख्यमंत्री और सीटू के उपाध्यक्ष ज्योति बसु ने 29 मई को प्रतिनिधियों को संबोधित किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग को मजदूरों और आवाम में एकता कायम करने के कर्त्तव्य को महसूस करना होगा और वह भी खास तौर से राज्य में अपना अस्तित्व कायम किए हुए वामपंथी सरकार के संदर्भ में. उन्होंने मजदूर वर्ग से जनवाद की रक्षा और लगातार बढ़ रहे अधिनायकवादी हमलों के विरोध में एक जुट होने का आह्वान किया.

सम्मेलन में कई प्रस्ताव अपनाएं गए जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं——पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल की लोकप्रिय सरकारों को बधाई, केन्द्र व राज्य संबंध, राज्य में विद्युत स्थिति, अधिनायकवादी खतरा और मजदूर वर्ग की भूमिका, जिम्बाबवे के नागरिकों को बधाई, कीमतों में बढ़ौतरी, बेरोजगारी, बोनस, मंहगाई के आंकड़ो में घांधली, नौकरी पेशा महिलाओं पर, ई एस. आई और प्रोविडेन्ट फंड, आसाम समस्या, हरिजन अत्याचार, तालाबंदी, नाजुक हालात वाले उद्योग, बंद फैक्ट्रियों को दोबारा खुलवाने, कुछ राज्यों में मजदूर वर्ग के संघर्ष के विरुद्ध आक्रामक कदम आदि पर प्रस्ताव.

सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक 470 सदस्यीय राज्य परिषद् चुनी गई. राज्य परिषद् ने अपनी पहली ही बैठक में एक 123 सदस्यीय वर्किंग कमेटी और 23 पदाधिकारी चुने इनमें मोहम्मद इस्माइल को अध्यक्ष और मनोरंजन राय को महासचिव चुना गया.

दम दम जेल मैदान में 30 मई को सम्मेलन के एक खुले सत्र के रूप में 70,000 मजदूरों, कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एक भारी रैली का आयोजन किया और सीटू की दसवीं वर्ष गांठ भी मनाई. सारे बड़कपुर औद्योगिक क्षेत्र और कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, नादिया तथा अन्य जिलों से हजारों मजदूरो

[शेष पृष्ठ दस पर]

काले अध्यादेश के विरूद्ध एकजुट संघर्ष

सीटू, एटक, एच एम. एस., बी. एम. एस., सर्वश्रमिक संघ, उटक, महाराष्ट्र राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन की संयुक्त संघर्ष कमेटी तथा इंटक के अतिरिक्त कुछ अन्य यूनियनों के आह्वान पर महाराष्ट्र की ट्रेड यूनियनों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में लागू किए गए एशेंशल सर्विस मेंटेनेंस अध्यादेश का विरोध करने के लिए 9 जून को बम्बई में हुए सम्मेलन में भाग लिया.

इस अध्यादेश से मजदूर वर्ग के आंदोलन पर हो रहे असर को जानते हुए सम्मेलन मे जुलाई में हो रहे राज्य विधान सभा में राज्यपाल के खुले भाषण के दिन ट्रेड यूनियनों का एक आम मिलाजुला मोर्चा तैयार करने का निश्चय किया गया है. मिलेजुले व्यापक संघर्ष की कड़ी में इस अध्यादेश के विरुद्ध हुआ यह पहला मोर्चा होगा. इस अध्यादेश के विरुद्ध राज्य के मुख्य औद्योगिक केन्द्रों में विरोध प्रदर्शन का निश्चय भी सम्मेलन में किया गया.

इस अध्यादेश से तथाकथित जरूरी सेवा जैसे बिजली, जल-पूर्ति, परिवहन, अस्पतालों आदि में हड़ताल पर रोक के अलावा राज्य सरकार को यह एकधिकार मिल जाता है कि वह किसी भी अन्य सेवा कहकर वहां के कर्मचारियों से हड़ताल का हक भी छीन ले. साथ ही यह अध्यादेश पुलिस को किसी भी मजदूर को बिना वारंट के गिरफ्तार करने तथा यदि वह हड़ताल में भाग लेता है या वह ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन देता है तो उस पर जुर्माना करने और गिरफ्तार करने की मनमानी शक्ति दे देता है

मजदूरों के प्रति मालिकों के कर्त्तव्य पर खामोश इस अध्यादेश में तालाबंदी, कम्पनी बद करने, मजदूरों की बरखास्तगी आदि के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है. इससे कभी भी काम बंद करना प्रबंधक की इच्छा पर निर्भर हो जाता है साथ ही अध्यादेश के पीछे केन्द्रीय सरकार के उद्देश्य भी साफ जाहिर हो जाते हैं. यह अध्यादेश मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सीधी चोट करता है.

9 जून को हुए सम्मेलन के प्रस्ताव में दमनात्मक प्रवृत्ति वाले, मजदूर वर्ग विरोधी इस अध्यादेश को बहुत गंभीरता से लिया गया है. अपने आपात्तकालीन अनुभव का हवाला देते हुए सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी के महासचिव पी के. कुरणे ने बताया कि किस प्रकार गरवारे नाइलान जैसी कम्पनी को भी जरूरी सेवा बताते हुए वहां हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया गया था तथा मजदूर आंदोलन को बुरी तरह उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई थी. उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश इस नई सरकार का मजदूर वर्ग पर और अधिक लादे जा रहे आर्थिक संकट के अधिनायकवादी कदम की शुरूआत है.

वक्ताओं ने इस अध्यादेश की तानाशाही प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए जल्द ही इसका व्यापक रूप में एकजुट हो विरोध करने का आह्वान किया. महाराष्ट्र और उड़ीसा में यह अध्यादेश पहले ही लागू हो चुक है और अब कर्नाटक में भी हाल ही में इस ओर कदम उठाया गया है. और यही प्रक्रिया चलती रही तो धीरे-धीरे अन्य सब राज्य भी इसकी चपेट में आ जाएंगे.

वेंकटरमण का बजट

[पृष्ठ दो से आगे]

पूंजीपतियों को रियायतें

वित्तमंत्री महोदय ने पूंजीपतियों को खुश करनेवाले अनेक प्रस्ताव पेश किये हैं. ऋण लेने के प्रावधान एकदम हानिरहित बना दिये है. अब निजी उद्योगों के मालिक बड़े आराम से सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेंगे और उन्हें यह भी भय नहीं रहेगा कि कहीं उनका कारोबार सरकारी संस्थाएं अपने नियंत्रण में न ले लें. वित्तमंत्री ने नये उद्योगों के लिएभी टूट-फूट खर्च में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी. लेकिन पूंजीपतियों के मुनाफे को रोकने के लिए किसी उपाय का प्रस्ताव मंत्रीजी ने नहीं किया. मुद्रास्फीति के चलते इन इजारेदारों ने बेतहाशा पैसा बटोर लिया है. सट्टेबाजों और चोर बाजारियों ने देश में जो समांतर अर्थव्यवस्था चला रखी है उसे नियंत्रित करने या उस पर रोकथाम के लिए कोई प्रावधान रखने की फुर्सत उन्हें नहीं मिली.

विज्ञापन, प्रचार सामग्री, और बिक्री बढ़ाने के लिए किये जानेवाले खर्च पर प्रतिबंध हटा कर बड़े व्यापारियों को और खुश किया गया है. छोटे और मझोले व्यापारिक घरानों को सहायता के नाम पर यह छूट दी गयी है. सही माने में यह छूट बड़े व्यापारी घरानों को दी गयी है. अब वे बड़े आराम से राजनीतिक पार्टियों को पैसा दे सकते हैं.

ग्रामीण निहित स्वार्थों को भारी रियायतें

चाय बागानों के मालिकों को छोड़कर कृषि संपत्ति को टैक्स से बरी करके वित्तमंत्री ने ग्रामीण निहित स्वार्थों को भारी रियायत दे दी है. इस सिलसिले में जो तर्क दिया गया है वह बड़ा विचित्र है. कहा गया है कि चूंकि जमींदार कर देने से इनकार कर देते हैं इसलिए उन पर लगने वाला संपत्ति कर हटा दिया गया है. वित्तमंत्री ने कहा कि "कृषि संपत्ति पर कराधान के वक्त सोचा गया था कि कृषि क्षेत्र के संपन्न लोगों से भी खासे साधन उपलब्ध हो सकेंगे. लेकिन हमारा पिछले दशक का (यहां जनता सरकार का उल्लेख नहीं है) अनुभव बेहद निराशाजनक रहा. कृषि संपत्ति पर लगाये करों से होनेवाली सालाना आय 1 करोड़ से भी कम रही, तथा लोग शिकायत करते रहे कि उन्हें तंग किया जाता है." इसमें शक नहीं कि छोटी मिल्कियतवालों को परेशान किया जाता रहा है. उचित तो यह होता कि यह छूट उन्हें ही दी जाती.

खाद, बीज, डीजल के दामों में बढ़ोतरी और उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई के सिवा आम किसान को इस बजट से क्या मिला ? मझोला किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पायगा. अन्य वस्तुएं भी उसे महंगी मिलेंगी. हां अपने उत्पादन पर दो रु० क्विंटल की दर से दो-चार पैसे ज्यादा मिल जायेंगे.

और जबरदस्त हमले

महंगाई के फलस्वरूप उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और मजदूरों की आय में और कटौती होगी. प्रबंधक उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार के अवसरों पर हमला करने को तैयार बैठे हैं. हमारी अर्थव्यवस्था को मौजूदा गतिरोध और रोजगार पर हो रहे हमलों से छुटकारा मिलने की कोई संभावना नहीं. हजारों लोग पहले ही छंटनी के शिकार होकर बेरोजगार हो चुके हैं.

इन हालात में विदेशी कर्जों में बढ़ोतरी होना, तथा 'रोजगार' बढ़ाने के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रियायतें देना लाजिमी बना रहेगा. यदि कहीं विश्व बैंक भी अपनी शर्तें मनवाने की जिद कर बैठा तो खाद्यान्न पर मिलने वाली रियायतों पर भी हमला हो सकता है. यह बजट बहुत ही खतरनाक आर्थिक हालात की ओर संकेत करता है लेकिन वित्तमंत्री ने उत्पादन शुल्क में छोटी-मोटी रियायतों पर खास जोर देकर इस सचाई पर परदा डालने की कोशिश की है.

जी. आई. सी. कर्मचारी संघर्ष की राह पर

जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन के प्रबंधकों और आल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन तथा अन्य यूनियनों में 12 और 13 जून के बीच हुई एक सभा में जी. आइ. सी. प्रबंधकों ने मौजूदा बहुत सी सुविधाओं में कटौती जैसे वृद्धि को वापस लेना. रिटायरमेंट की उम्र कम करना और मंहगाई भत्ते पर सीमा लगान आदि की पेशकश की. बोनस का कहीं जिक्र नहीं था.

ए. आइ. आइ. ई. ए. ने वेतन ढ़ांचे में सुधार करने पर जोर दिया, किन्तु कटौती पर प्रबंधकों के अटल बने रहने के कारण समझौता नहीं हो पाया. इस पर इंश्योरेंस उद्योग के सभी ट्रेड यूनियन संगठनों के आह्वान पर जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी 14 जून को इस मसले के खिलाफ एक संघर्ष छेड़ने के लिए इकठ्ठा हुए. इस सभा में 17 जुलाई को प्रबंधकों के मौजूदा अधिकारों को खत्म करने के प्रस्ताव के खिलाफ उचित वेतन की मांग के पक्ष में देश-व्यापी आंदोलन छेड़ने का भी निश्चय किया गया है. यदि जी. आइ. सी. प्रबंधक व सरकार जल्द किसी उचित फैसले पर नहीं पहुंचेगी तो यूनियनें अपने इस आंदोलन को और अधिक व्यापक व मजबूत बनाने को मजदूर होगी.

पश्चिम बंगाल सीटू ...

[पृष्ठ नौ से आगे]

छोटी-छोटी टुकड़ियों व बड़े-बड़े जुलूसों दोनों रूपों में आकर इकट्ठे हुए. 24 परगना जिले के किसानों ने भी जुलूसों की शक्ल में आकर रैली में भाग लिया.

इस रैली की अध्यक्षता मोहम्मद इस्माइल ने की और ज्योति बसु, मनोरंजन राय, नृपेन घोष, कृष्णपद घोष, मोहम्मद इस्माइल तथा अन्य नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए.

उत्तर प्रदेश

सी. ई. एल. मजदूरों की हड़ताल समाप्त

सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सी. ई. एल.) मजदूरों की तीन महीनों से चल रही हड़ताल सी. ई. एल. कर्मचारी यूनियन (सीटू) और प्रबंधकों में 2 जून को एक समझौता हो जाने के बाद समाप्त कर दी गई. मजदूरों ने अपने मांग पत्र के समर्थन में 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी थी. इस मांग पत्र पर कोशिशों के बावजूद भी हड़ताल से पहले कोई समझौता न हो पाया था. मजदूर जन कोष के गलत उपयोग में उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जांच, आधिकारिक शक्तियों का नाजायज फायदा उठाने, बोनस की मांग, पदोन्नति नीति लागू करने, सी. सी. ए., ई. एस. आइ. सी. से छूट, उत्पादन प्रोत्साहन योजना और पिछले समझौते को पूरी तरह लागू करने की मांग कर रहे थे. प्रबंधकों ने यह स्वीकार किया कि हड़ताल में भाग लेने वाला कोई भी मजदूर किसी प्रकार की ज्यादतियों का शिकार नहीं होगा. यह हड़ताल 15 दिन पहले समाप्त हो जाती

देहरादून परिवहन मजदूर विजयी

देहरादून जिले की निजी बस सेवा के चालक व कंडक्टर वेतन-वृद्धि और कार्य व निर्वाह के बेहतर हालात के लिए काफी अर्से से संघर्षरत थे. जिला देहरादून ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन (सीटू) ने प्रबंधकों को यह नोटिस दिया था कि यदि उनकी मांगें 1 मई तक पूरी न की गई तो वे हड़ताल करने को मजबूर होंगे. इसके परिणाम स्वरूप प्रबंधकों और यूनियन में एक समझौता हुआ.

इस समझौते के तहत ड्राइवरों को 280 रुपया प्रति माह और 10 रुपये वार्षिक वृद्धि तथा कडक्टरों व क्लीनरों आदि को 175 रुपया प्रति माह तथा 7 रुपये वार्षिक वृद्धि होगी. उन्हें वर्दियां भी दी जाएंगी. साथ ही दैनिक भत्ते के रूप में ड्राइवरों को 4 से 8 रुपये तक तथा कंडक्टरों को 3 से 5 रुपये तक दिया जाएगा. यह राशि उनके मार्ग पर निर्भर करती है. यह समझौता 1 अप्रैल 1980 से लागू माना जाएगा और तीन वर्षों तक चलेगा.

हर्ब्स मजदूरों का दमन

बताया जाता है कि इंडियन हर्ब्स रिसर्च एंड सप्लाइ कम्पनी अपना टेक्स बचाने के लिए आठ भिन्न-भिन्न नामों के तहत कर रही है. 15 लाख रुपये प्रतिमाह बिक्री में से 40 प्रतिशत मुनाफा कमाने वाली यह कम्पनी आयकर विभाग के साथ धोखा कर रही है. मजदूर यूनियन के अनुसार यह कम्पनी कई प्रकार के अपराध कर रही है. साथ ही कम्पनी के प्रबंधकों ने 14 मजदूरों की छंटनी भी कर दी जबकि पैकिंग का आधा काम मजदूरों की कमी के कारण बाहर से करवाया जाता है. मजदूरों की छंटनी तथा उन्हें झूठ आरोपों में फंसाने के काम में प्रबंधक भाड़े के गुंडों का सहारा लेने में भी नहीं चूकते हैं. केंद्रीय औद्योगिक मंत्री को दिए अपने एक ज्ञापन में इंडियन हर्ब्स वर्कर्स यूनियन ने इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले की जांच की जाए तथा कम्पनी की इन मजदूर विरोधी नीतियों का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए.

बिहार

अराजपत्रित कर्मचारियों का सफल संघर्ष

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 90 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 14 और 15 मई को हुई दो दिन की हड़ताल में भाग लिया. उच्च न्यायालय, अस्पतालों, पी. एच. आर. डी., पी. डब्लू. डी., सिविल कोर्ट, जिला सब डिविजनल दफ्तरों व खंडों का काम ठप्प हो गया था. पटना सचिवालय सूना पडा था. वहां केवल पुलिस वालों की भीड़ नजर आती थी.

फेडरेशन सरकार से 26 दिसम्बर 1979 को हुए समझौते को लागू करने पर जोर दे रही थी. मई में हुई एन. जी. ओ. की सांकेतिक हड़ताल के बाद 17 मई को फेडरेशन की एक्शन कमेटी की एक फौरी सभा में इस संघर्ष को और अधिक व्यापक रूप देने का निश्चय किया गया. साथ ही यह भी तय हुआ कि यदि उनकी मांगें पूरी न की गई तो वे 26 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे. एक्शन कमेटी का दृढ़ निश्चय और हड़ताल की तैयारी देख नौकरशाही हिल उठी. हड़ताल से एक दिन पहले उन्होंने समझौता कर लिया और हड़ताल खत्म कर दी गई

समझौते के अनुसार कर्मचारियों को 1 अप्रैल 1980 से उनके वेतनमानों के मुताबिक अंतरिम राशि दी जायेगी. निम्न स्तरीय क्लर्कों (एल. डी. सी.) और उच्च स्तरीय क्लर्कों (यू. डी. सी.) के वेतनमानों को 1 मई से मिला दिया गया है जिससे 70 हजार कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा.

पंजीकरण विभाग के एक हजार से अधिक पदों को नियमित कर दिया गया है. साथ ही कर्मचारियों को चिकित्सा, मंहगाई, आवास भत्ता आदि के लिए अधिक सुविधाएं दी जाएंगी.

केमिकल मजदूरों की जीत

बगाही रतनपुर की सेंट्रल केमिकल कार्पोरेशन के मजदूरों जिनका काफी अर्से से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी था अंततः वेतन में 20 रुपये की बढोतरी, आठ घंटों का काम, 8.33 प्रतिशत बोनस, वर्दी, अतिरिक्त काम भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्राप्त करने में सफल हुए हैं. इस मजदूर आंदोलन का नेतृत्व सीटू कर रही थी.

साथ ही बेतिया के प्रिया सिनेमा के कर्मचारियों ने 6 जून को एक समझौते के बाद सीटू यूनियन के तहत रहकर बोनस, मंहगाई भत्ता तथा बकाया वेतन आदि भी प्राप्त किया है.

त्रिपुरा मुख्यमंत्री सहायता कोष में अनुदान

सीटू की बिहार राज्य कमेटी ने त्रिपुरा में हाल ही में हुए दंगों के पीड़ितों के लिए 500 रुपये त्रिपुरा मुख्यमंत्री सहायता कोष में अनुदान दिए हैं.

कामगार महिला दिवस मनाया गया

तमिलनाडु में आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमेन के आह्वान पर कामगार महिलाओं की संस्थाओं पर प्रकाश डालने के लिए 28 अप्रैल को एक दिवस मनाया गया. इस दिन तमिलनाडु में मदुराई, कोयंबतूर और सालेम में कामगार महिलाओं ने बिल्ले पहने व रैलियां और मीटिंगें आयोजित कीं. त्रिची, तंजाबूर, डिंडीगूल और अरूपुकोट्टई में गोष्ठियां की गईं. मद्रास में बालू गार्मेंट्स, टेबलेट्स एंड पेस्ट कंट्रोल और 'थार' ठेका कामगार महिलाओं ने एक धरना आयोजित किया जिसमें 300 से भी ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया. बाद में एक रैली हुई. इस अवसर पर काफी संख्या में पोस्टर व पर्चे प्रकाशित किए गए. विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए. राज्य सरकार ने दियासलाई मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन कमेटी का प्रस्ताव रखा है जिसमें कामगार महिलाओं का प्रतिनिधित्व मैथली शिवरमण करेंगी.

फरीदाबाद (हरियाणा) में कामगार महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 28 अप्रैल को जिला प्रशासन को अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन दिया. ज्ञापन में अन्य के अलावा स्थानीय बस सेवा और कुछ आवश्यक वस्तुओं को फैक्ट्री गेट पर एक दाम पर उपलब्ध कराने की मांग की गई थी.

भिलाई (मध्य प्रदेश) में एक जुलूस निकाला गया जिसमें 200 से भी ज्यादा कामगार महिलाओं ने भाग लिया. बाद में एक रैली हुई.

कानपुर (उत्तर प्रदेश) में एक सभा आयोजित की गई जिसमें अन्यों के अलावा ठेका मजदूर, घरेलू नौकर और प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं ने भाग लिया. कामगार महिला समिति की अध्यक्षा ने इस दिन की मांगों पर प्रकाश डाला.

सीटू का नवीनतम प्रकाशन

खदानों में कामगार महिलाओं की दशा

[प्रेस में]

अनुमानित कीमत 60 पैसे

लिखें:-

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

श्री वी. वी. गिरि

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 25 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी व्यक्तियों में से एक, श्री वाराह गिरि वेंकट गिरि के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है.

श्री गिरि ने भारत में रेल मजदूरों के आंदोलन का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था.

भारत का मजदूर श्री गिरि को उनके द्वारा 1950 के दशक ट्राइब्युनल के फैसले में केंद्र द्वारा किए जाने वाले संशोधन का विरोध करते हुए इस्तीफा देने के साहसपूर्ण कार्य तथा उनके द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए किए गए कामों के लिए हमेशा याद रखेगा.

सीटू श्री गिरि के शोक संतप्त परिवार को अपनी हार्दिक संवेदना भेजती है.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980		
	फर.	मार्च	अप्रै.
बिहार			
जमशेदपुर	350	358	367
झारिया	350	357	358
कोडर्मा	399	399	397
मोंघाइर	393	394	397
नोआमुंडी	360	362	362
गुजरात			
अहमदाबाद	357	359	360
भाव नगर	380	387	388
हरियाणा			
यमुना नगर	395	405	403
जम्म व काश्मीर			
श्रीनगर	361	367	387
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	387	394	400
भोपाल	369	374	374
ग्वालियर	383	392	393
इंदौर	384	387	390
महाराष्ट्र			
बंबई	373	375	381
नागपुर	363	363	365
शोलापुर	381	383	383
पंजाब			
अमृतसर	389	391	393
राजस्थान			
अजमेर	380	385	388
जयपुर	392	392	395
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	368	370	374
महारनपुर	377	383	383
वाराणसी	423	432	433
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	379	387	387
कलकत्ता	348	356	362
दार्जीलिंग	313	312	311
हावड़ा	340	347	347
जलपाइगुरी	309	312	313
रानीगंज	367	373	377
दिल्ली	393	398	401
भारत	369	373	375

भारतीय नाविकों का विश्वस्तरीय संघर्ष

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मजदूर फैडरेशन के जोर देकर यह कहने कि 'फ्लेग आफ कनवीनिएंस' जहाजों पर काम करने वाले सभी नाविकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेतन मिलना चाहिए भारतीय नाविकों को दुविधा में डाल .

विदेशी जहाजों के लिए भर्ती किए गए भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम वेतन पाते हैं. ये भर्तियां जहाजरानी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हैं तथा इनसे बिना पूंजी लगाए सरकार राजस्व प्राप्त करती है. आइ. टी. एफ. अधिकारियों ने बहुत से जहाज पकड़े. इसमें 'साउथ रेनबो' 'पेस मेकर' 'हिविसकस' बहुत जाने माने जहाज हैं.

इन जहाजों के भारतीय नाविकों के अनिच्छुक होते हुए भी नाविकों, आइ. टी. एफ. और मेसर्स वालेम शिपमेनेजमेंट आफ हांगकांग की जहाजरानी कम्पनी में एक समझौता किया गया. नाविक अपने भविष्य के प्रति बहुत चिंतित थे. किन्तु जब वे लोग स्वदेश लौटे तो उक्त प्रबंधकों ने नाविकों को आइ. टी. एफ. समझौते के तहत कमाए अतिरिक्त धन को (जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है) वापस करने को कहा, केन्द्रीय सरकार जहाजरानी मंत्री ने नाविकों की सहायता करने के बजाय प्रबंधकों का ही साथ दिया.

भारतीय नाविक इस बदलावे के कारण चिंतित हैं. सभी भारतीय नाविकों को इस चंगुल से निकालने के लिए फारवर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया (सीटू) की कार्यकारी कमेटी ने विश्व-स्तरीय संघर्ष करने का निश्चय किया है. उन्होंने सभी भारतीय बंदरगाहों पर 10 जून को अपने दससूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में एक दिन का 'मांग दिवस' मनाया. इन दस सूत्रीय मांग में रोजगार देने की आकस्मिक पद्धति समाप्त करना, पूरे वर्ष भर के लिए भारतीय नाविकों को रोजगार का आश्वासन देना बेरोजगारी भत्ता ('साइन आफ' से 'साइन आन' के दौरान 700 रुपये महीना), आई. एल. ओ. के अनुसार 78 पौंड स्टर्लिंग न्यूनतम वेतन, दोहरी चिकित्सा जांच के खात्में व परिवार को चिकित्सा सुविधा देना, जहाजरानी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना व 20% बोनस की मांग आदि शामिल है.

इसी प्रकार का आह्वान वाटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन आफ इंडिया ने भी हाल ही में हुए कोचीन सम्मेलन में किया था. इसमें 2000 से अधिक भारतीय नाविकों ने भाग लिया जिसका आयोजन पांच सीटू यूनियनों फारवर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया, कलकत्ता पोर्ट एंड शोर मजदूर यूनियन, डाक श्रमिक एसोसियशन, कलकत्ता तिफिन क्लब कर्मचारी यूनियन और सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने मिलकर किया था. कलकत्ता, मद्रास कोचीन, गोआ, कांदला के गोदी मजदूरों ने मिलकर बहुत सी सभाएं बुलाई, यूनियन ने अपने संघर्ष को और अधिक अटूट बनाने के लिये जहाज बंद का निश्चय किया है. डब्लू. टी. डब्लू. एफ. आइ. के निर्णय के आधार पर पांचों यूनियनों ने अपने मांग पत्र के समर्थन में 28 जून को कलकत्ता में एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया है.

ग्रिंडलेज बैंक में मशीनीकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टे आर्डर दिया

भारतीय सरकार के इस बैंक का मामला निर्णय के लिए दे देने पर दिल्ली के प्रबंधकों ने बैंक में मशीनीकरण शुरू कर देने का निश्चय किया. इससे कर्मचारियों के बीच रोष पैदा हो गया है. हैरानी की बात यह है कि यूनियन को स्थानीय ए. आइ. बी. ई. ए. के नेतृत्व ने प्रबंधकों के सामने यह मामला उठाने से इंकार कर दिया.

सत्यपाल गोयल के नेतृत्व में कुछ कर्मचारियों ने पहलकदमी की ओर दिल्ली के प्रथम श्रेणी के सब-जज श्री जे. के. पाली की अदालत में एक याचिका पेश की. 29 मई को स्टे आर्डर देते हुए जज महोदय ने प्रबंधकों से 17 जुलाई को कारण बताने का आदेश दिया.

इस स्टे आर्डर से दिल्ली के ग्रिंडलेज बैंक के कर्मचारियों में एक उत्साह की लहर दौड़ गई और उन्होंने स्थानीय यूनियन के नेतृत्व की निन्दा करते हुए कहा कि वे कर्मचारियों के इस न्यायपूर्ण उद्देश्य को कैसे नजरअंदाज कर सकी. अभी तक यूनियन का नेतृत्व इस मामले में कोई भी संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहा है.

सीटू की दसवीं वर्ष गांठ

दिल्ली और उसके आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों के 600 से अधिक मजदूरों ने सीटू की दसवीं वर्ष गांठ मनाने के लिए सीटू केन्द्रीय कार्यलय में आयोजित एक रेली में भाग लिया.

संसद सदस्य और सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने पिछले दस वर्षों में सीटू की उपलब्धियों पर विस्तार से बात की. सीटू सचिव एम. के. पंधे ने भी सभा में वक्तव्य दिया. सभा के बाद एक फिल्म 'लेनिन इन अक्टूबर' दिखाई गई जिसकी सभी ने सराहना की. इस अवसर पर सीटू ने 'सीटू के दस वर्ष' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय किया है.

इसी प्रकार की रैलियां येलान्दु कोलियरी (सिंगारेनी) और कुरनूल आंध्र प्रदेश में भी आयोजित की गईं.

सीटू का नया प्रकाशन

कोयला खदानों में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का

चेहरा बेनकाब

मूल्य : 40 पैसे

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड नई दिल्ली-110001

कर्नाटक

मजदूर वर्ग के जनवादी अधिकारों पर हमले

आम जनता की बुनियादी समस्याओं का हल करने में नाकामयाब कर्नाटक सरकार ने जनता के विरुद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इस दिशा में पहला कदम मजदूर वर्ग पर हमलों को और तेज करना है.

इसके पक्ष में उदाहरणों की कोई कमी नही है. एक एकाधिकारी मैसर्ज बांगूर की चिकमंगलूर की सम्से एस्टेट के मजदूरों को जो तीन निकाले गए मजदूरों की बहाली व अन्य मुद्दों के समर्थन में दो महीनों से भी ज्यादा से हड़ताल पर हैं, मई महीने में पुलिस ने बर्बरता से मारा-पीटा. मजदूर यूनियन के सहायक सचिव के. सुकुमार को बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया गया और एस्टेट के दफतर में पुलिस द्वारा सताया गया. उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट तक ने उसको चिकित्सा देने से इनकार कर दिया.

माइको के बहुराष्ट्रीय घमंडी प्रबंधकों ने मजदूरों को, जो 88 दिन की सफल के हड़ताल के बाद 5 जनवरी को काम पर लौटे थे, विभाजित करने का षड़यंत्र रचा और इंदिरा कांग्रेस सरकार तथा पुलिस के साथ सजिश करके 23 मजदूरों पर गुंडा से हमला करवाया. माइको एंप्लाईज एसोसिएशन ने 17 मई को एक दिन की हड़ताल अपनी शिकायतों पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित की थी. प्रबंधकों ने किसी भी समझौतावार्ता के लिए मना कर दिया. दूसरी ओर पुलिस ने राज्य सीटू अध्यक्ष एस. सूर्यनारायण राव को राज्य निष्कासन के आदेश दे दिए जिसके खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया.

इंदिरा कांग्रेस सरकार खुल्लमखुल्ला इंडियन टोबेको कंपनी बंगलौर के बहुराष्ट्रीय प्रबन्धकों का समर्थन कर रही है और मजदूरों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. दस साल पहले इस कंपनी में 3000 मजदूर काम करते थे और प्रतिदिन 2 करोड़ 60 लाख सिगरेट बनती थीं. लेकिन इस समय केवल 2200 मजदूर काम करते हैं तथा 4 करोड़ सिगरेट बनती हैं.

बहुराष्ट्रीय कंपनी, इंदल अल्युमीनियम फैक्ट्री, बैलगांव एक और उदाहरण है जहां मजदूरों को जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकार नहीं दिए जाते. इसमें 1500 से भी ज्यादा मजदूर काम करते हैं जिसमें 500 ठेका मजदूर शामिल हैं. प्रबधक आर. जी. तालेकर के यूनियन अध्यक्ष चुने जाने को सहन नही कर सके. कई तरह से मजदूरों पर हमले शुरु हो गए. मजदूर निर्वाह व कार्य के लिए बेहतर हालात व अन्य मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हाल ही में 22 मजदूरों को कैंटीन में गंदा खाना खाने के कारण हस्पताल में भर्ती किया गया. चाए में कपड़े धोने का सोडा पाया गया. मजदूर संघर्ष चल रहा है और प्रबंधकों से वार्ता का कोई फल नहीं निकला. प्रबंधकों ने 29 अप्रैल को तालाबंदी कर दी. मजदूरों व उनके परिवारों ने 8 मई को एक प्रदर्शन आयोजित किया. लेकिन पुलिस ने बिना किसी कारण के लाठी चार्ज कर दिया जिससे महिलाओं सहित अनेक मजदूर घायल हुए. करीब 300 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया. इंदल मजदूर कालोनी अब पुलिस कालोनी बन गई है.

राज्य के किसी भी हिस्से में जब कभी मजदूर संघर्ष होते हैं तो सरकार पुलिस कानून की धारा 35 मजदूर संघर्ष कुचलने के लिए लगा देती है. जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों को किसी न किसी तरह छीन लेना एमर्जेंसी से पहले के समय की याद दिलाता है.

आंध्र प्रदेश

बी. एच. पी. वी. में तालाबंदी समाप्त

एक सार्वजनिक उद्योग भारत हेवी प्लेट वेसेल्ज (बी. एच. पी. वी.), विशाखापटनम, के प्रबंधकों ने 26 मई को तालाबंदी घोषित कर दी थी जिसे 12 जून को एक त्रिपक्षीयवार्ता में समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया.

इससे पहले 24 अगस्त 1978 को यूनियन और प्रबंधकों के बीच वेतन वृद्धि आदि पर एक समझौता हुआ था. इस समझौते में एक यह धारा भी थी कि जब कभी भेल (बी. एच ई. एल.) में समझौता होगा और यदि यह बी. एच. पी. वी. से अच्छा हुआ तो उसे ही बी. एच. पी. वी. में भी एक जनवरी 1978, यानि जिस दिन पहला समझौता समाप्त हुआ था, से ही लागू किया जाएगा.

जब इस साल जनवरी में भेल में समझौता हुआ तो बी. एच. पी. वी. नेशनल एंप्लाईज यूनियन ने भेल के वेतन मानों को बी. एच. पी. वी. में लागू किए जाने की मांग की. लेकिन प्रबंधक पहले समझौते को तोड़ते हुए भेल समझौता में रद्दोबदल करना चाहते थे. समझौतावार्ताओं का कोई फल नहीं निकला.

सभी प्रयासों का कोई फल न निकलने के कारण 29 अप्रैल से मजदूरों ने काले बिल्ले पहनने शुरू कर दिए. लेकिन प्रबंधकों ने गलत वक्तव्य जारी करके इसका जबाव दिया. इसने 7 यूनियन कार्यकर्त्ताओं को नौकरी से निकाल दिया, 11 मजदूरों को निलंबित कर दिया, अनेक मजदूरों को चार्जशीट जारी की तथा वेतन काटना शुरु कर दिया. प्रबंन्धकों ने संघर्ष के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आर्डर ले लिया और इसका फायदा उठाकर कर्मचारियों पर दोष लगाते हुए 26 मई को फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी.

सिंगारेनी मजदूरों का पहला सम्मेलन

सिंगारेनी कोलियरीज एंप्लाईज यूनियन (सीटू) का पहलास लाना सम्मेलन 30 मई को येलांडु कोलियरीज में आयोजित किया गया जिसमें सिंगारेनी कोलियरीज के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. के. जार्ज ने अध्यक्षता की. पारसा

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों ने क्या पाया ?

त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों को बहुत-सी सुविधाएं हासिल हैं जिनमें मुख्य हैं—ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों की यूनियनों को मान्यता प्राप्त होना, आपातस्थिति में धारा 311 (2) (स) के तहत जिन लोगों की छटनी कर दी गई थी उनकी बहाली, पुरानी सरकार द्वारा अपनाई गई दमनात्मक नीति की समाप्ति, बरखास्तगी के सभी मामलों, सालाना बढौतरी को जब्त किए जाने, कार्यकुशलता में बाधा आदि का खात्मा, नियुक्ति के मामलों में वामपंथी सरकार द्वारा अपनाई गई खास नीति, एक सही तबादला नीति का हाल ही में लागू होना, काम के अच्छे हालात देने और वेतनमानों के अंतर को कम करने के लिए एक वेतन आयोग की नियुक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का साथ देने के लिए उन्हें विशेष छूट, वर्ग पांच के कर्मचारियों के लिए मुफ्त आवास, सार्वजनिक कर्मचारियों का राशन भत्ता बढ़ाना, चौकीदारों (गावों के रक्षकों) के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी.

इस तरह वामपंथी सरकार संघर्षरत कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति करके उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए कृत संकल्प है. साथ ही यह एक ऐसी सरकार बनाना चाहती है जिसकी नीव कर्मचारियों के विश्वास और सहयोग पर खड़ी हो.

केरल कर्मचारियों को कार्यकुशलता बोनस

केरल की वामपंथी और जनवादी सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों के लिए 500 रु. से 3000 रुपये तक के नकदी इनामों के रूप में कार्यकुशलता बोनस देने की एक नई योजना तैयार की है. यह योजना सरकार के हाल ही के प्रशासन को ठीक-ठाक करने के उपलक्ष्य में है. मुख्य मंत्री ई. के. नयनार ने कहा है कि नकदी इनामों के लिए अपने प्रशासनिक खर्च की बचत के सकारात्मक योगदान के आधार पर विभिन्न विभागों में से औसतन 200 सेवारत कर्मचारियों को चुना जाएगा.

आसाम

राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर घातक हमले

सीटू की गोहाटी जिला कमेटी की बृहत्तर बैठक 8 जून को गोहाटी में हुई जिसमें विदेशी नागरिकों को लेकर नौ महीनों से चल रहे राज्य में आंदोलन से उत्पन्न मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की गई. एक प्रस्ताव में कहा गया है कि गोहाटी युनिवर्सिटी के रीडर, 'कालाखार' के संपादक व प्रसिद्ध शिक्षाविद् डा० हीरेन गोहाइं पर घातक हमलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य में मौजूदा आंदोलन न तो शांतिपूर्ण है और न ही अहिंसक है

चार सौ से भी ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं व मजदूरों पर लगातार हमले, जिसमें भूवेन बरबारा व आठ अन्यों पर घातक हमले शामिल हैं, जो एक और 26 मई को किए गए. राजनीतिक नेताओं और समर्थकों का सामाजिक और आर्थिक बायकाट यह साफ दर्शाता है कि आंदोलन के आयोजकों में ऐसी ताकतें हैं जो वाम पंथी ताकतों पर आतंक फैलाने में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं. उनके वामपंथ के खिलाफ अंध नजरिये ने नो महीने के आंदोलन से उत्पन जनता की कठिनाइयों के प्रति भी उन्हें उदासीन बना दिया है. सीटू की गोहाटी जिला कमेटी ने राजनीतिक नेताओं व मजदूरों तथा डा० गोहाइं पर घातक हमलों की निंदा करते हुए ऐसे लगातार और असंख्य हमलों को रोकने में नाकामयाबी के लिए सरकार की आलोचना की.

जिला कमेटी ने सभी जनवादी ताकतों और ट्रेड यूनियन संगठनों से कथित आतंककारी ताकतों के खिलाफ हिम्मत से व एकजुट होकर आगे आने की अपील की है. कमेटी ने सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों की आसमान छूती कीमतों और मजदूरों के वास्तविक वेतन में कमी के खिलाफ संयुक्त आंदोलन चलाने का भी आह्वान किया.

इसने सरकार से भी यह अनुरोध किया कि आसाम में मौजूदा आंदोलन का तुरंत राजनीतिक हल करे. कमेटी ने आंदोलन के नेताओं से यह अपील की कि वे वास्तविकताओं से दूर न जाएं और अपनी मांगों पर बातचीत के द्वारा समझौते के लिए आगे आएं

जम्मू व कश्मीर

सरकारी कर्मचारी फेडरेशन का पुनर्गठन

हाल ही में कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की फेडरेशन के एक सौ से भी अधिक पदाधिकारियों व कार्यकर्त्ताओं की श्रीनगर में फेडरेशन की पुनर्रचना व पुनर्गठन के लिए एक बैठक हुई. इस बैठक में फेडरेशन की मुख्य यूनियनों व एसोसिएशनों ने भाग लिया. बैठक में एक सम्मेलन आयोजित करने और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन वृद्धि आदि के संघर्षों का संचालन करने का फैसला लिया.

बैठक में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी संपथ प्रकाश के नेतृत्व में पूरा विश्वास प्रकट किया गया और अब्दुल माजिद खां को फेडरेशन तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. बैठक में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सदस्यों की पूरी एकता कायम करने के लिए दृढ़ निश्चय किया गया. अब्दुल माजिद मुजतर और मौहम्तद शफी खान संगठन कमेटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी चुने गए.

नवंबर में अखिल भारतीय कोयला कनवेंशन

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ कोल यूनियंस (सीटू) की बैठक 23 जून को रानीगंज में हुई. बामापद मुखर्जी ने मीटिंग की अध्यक्षता की.

कोआर्डिनेशन कमेटी के संयोजक रोबिन सेन ने मुद्दों पर प्रकाश डाला और सीटू से संबद्ध तथा मैत्रीपूर्ण सभी यूनियनों की ओर आगे तालमेल बैठाने की जरूरत पर जोर दिया.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने पिछले वेतन समझौते के बाद की घटनाओं की समीक्षा की और बताया कि समझौते की कई धाराओं को अभी लागू नही किया गया है. उन्होंने समझोते व अन्य संबद्ध मुद्दों के पूरी तरह लागू होने की गारंटी के लिए संघर्ष को जारी रखने की महत्ता पर जोर दिया.

विभिन्न कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले साथियों ने अपनी गतिविधियों तथा अपने क्षेत्रों में चलाए गए एकजुट आंदोलनों की रिपोर्ट पेश की.

मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि यूनियनों के सदस्यता अभियान को और तेज किया जाय ताकि सीटू की संगठित शक्ति काफी बढ़ जाए.

मीटिंग ने एन. सी. ओ. ई. ए. के जनरल सेक्रेटरी जे. के. बोस को कोयला वेतन समझौते के लागू करने पर बनी द्विपक्षीय कमेटी के लिए सीटू का प्रतिनिधि नामजद किया (विकल्प सदस्य एस. सुदेवन).

मेडिकल सुविधाओं पर बनी द्विपक्षीय कमेटी के लिए आंध्र प्रदेश सीटू के अध्यक्ष पारसा सत्यानारायण को नामजद किया गया.

सीटू संघर्ष कोष के लिए अभियान की कमेटी ने समीक्षा की और यह फैसला लिया गया कि सभी यूनियनें जितनी जल्दी हो सके अपने हिस्से की अदायगी पूरी करें.

सैंक्टोरिया में ई. सी. एल. कर्मचारियों द्वारा इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर के खिलाफ शुरू किए गए एकजुट संघर्ष का कमेटी ने समर्थन किया.

नवंबर के महीने में रानीगंज, आसनसोल कोयला क्षेत्र में अखिल भारतीय कोयला मजदूर कनवेंशन आयोजित करने का फैसला लिया गया. कनवेंशन की तारीखें संबद्ध साथियों से सलाह करके संयोजक द्वारा बाद में घोषित की जाएंगी.

कनवेंशन के तैयारी कार्य की समीक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि कोआर्डिनेशन कमेटी की अगली बैठक सितंबर महीने में दिड्डी-ए कोलियरी (बिहार) में होगी.

त्रिपुरा फंड के लिए सीटू की अपील

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने सीटू से संबद्ध सभी यूनियनों के नाम एक अपील जारी की है कि वे साम्राज्यवादी ऐजेंटों की शह पर उपद्रवकारी तत्वों द्वारा की गई आगजनी व लूटपाट से बेघर हुए लाखों लोगों को पुन: बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता दें.

त्रिपुरा की जनता को मौजूदा दशा का सामना करने के लिए कपड़ों और दवाइयों आदि की भी जरूरत है.

सीटू की यूनियनों को इस मौके पर पहल करनी चाहिए और उनसे जो भी बन पड़े बिना किसी देरी के वे उन्हें भेजें ताकि षड़यत्रकारियों के ये अभागे शिकारों को जितनी जल्दी हो सके पुन: बसाया जा सके.

सभी प्रकार की सहायता मुख्य मंत्री सहायता कोष, अगरतला, त्रिपुरा, के नाम भेजें.

सीटू यूनियनों द्वारा भेजी गई सहायता की रिपोर्ट सीटू केंद्र भी भेजें.

सिंगारेनी...

[पृष्ठ चौदह से आगे]

सत्यनारायण ने अपनी सचिव की रिपोर्ट में यूनियन के 30 जून 1978 को बनने के बाद की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और यह रिपोर्ट अपना ली गई. सम्मेलन में राज्य में कोयला खदान मजदूरों की समस्याओं पर प्रस्ताव अपनाए गए.

सम्मेलन में एक नयी प्रबंधक कमेटी बनी जिसके के. जार्ज अध्यक्ष और पारसा सत्यनारायण राव महासचिव निर्वाचित हुए.

अखिल भारतीय जूट मजदूर सम्मेलन
27-28 सितंबर 1980
कानपुर (यू. पी.)

संपादक मंडल
बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति मनोरंजन राय
निरेन घोष सुधिन कुमार
एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित